GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

**RAJYA SABHA**

**STARRED QUESTION NO. 139**
**ANSWERED ON 10.12.2021**

**RAILWAY STATIONS SHUTDOWN DURING LOCKDOWN**

139 SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many railway stations were shut during lockdown;

(b) if so, the details thereof;

(c) the future plans for such railway stations;

(d) whether it is also a fact that there are many places in the country where railway land has been encroached by poor people for staying; and

(e) if so, the details thereof and the action taken by the Railway for their evacuation and settlement for these poor people?

**ANSWER**

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

*****

**STATEMENT** REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (e) OF STARRED QUESTION NO. 139 BY SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 10.12.2021 REGARDING RAILWAY STATIONS SHUTDOWN DURING LOCKDOWN

(a) to (c) No, Sir. No station on Indian Railways was shut down during lockdown. As part of nationwide lockdown, all passenger train services on Indian Railways were suspended w.e.f 23rd March, 2020 as per the extant guidelines issued by Government of India. However, freight services were continued to ensure supply of essential commodities to different parts of the country.

(d) and (e) As on 31.03.2021, a total of 810.31 Hectare of railway land was under encroachment which includes encroachment by poor people.

The Government identifies such encroached land by carrying out regular inspections at various levels. In case, any trespass is noticed which may eventually lead to encroachment, it is removed then and there.

If the encroachments are of temporary nature (soft encroachment) in the shape of jhuggies, jhopries and squatters, the same are got removed in consultation and with the assistance of Railway Protection Force (RPF) and local civil authorities. For old encroachments, where party is not amenable to persuasion, action is taken under Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (PPE Act, 1971), as amended from time to time.

Rehabilitation and settlement of encroachers on Railway land is not possible due to Railways' operational and infrastructural needs. Housing is a State subject and responsibility for providing alternative sites for rehabilitation/ resettlement as well as bearing cost for the same, vest with the State Governments or the Urban Local Bodies concerned.

During the last three years i.e. 2018, 2019, 2020 & current year i.e 2021(upto November), a total of 5290 joint drives were conducted by Engineering Department assisted by RPF wherein a total of 10832 encroachments have been removed from Railway area.

*****

**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**10.12.2021 के**

**तारांकित प्रश्न सं. 139 का उत्तर**

**लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशनों को बंद किया जाना**

***139 श्री कामाख्या प्रसाद तासाः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि लॉकडाउन के दौरान कई रेलवे स्टेशन बंद थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे रेलवे स्टेशनों हेतु भावी योजनाएँ क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ रेलवे की भूमि का गरीब लोगों द्वारा रहने हेतु अतिक्रमण किया गया है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गरीब लोगों को वहाँ से हटाने व उन्हें अन्यत्र बसाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशनों को बंद किए जाने के संबंध में दिनांक 10.12.2021 को राज्य सभा में श्री कामाख्या प्रसाद तासा के तारांकित प्रश्न सं.139 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): जी नहीं। लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल में कोई स्टेशन बंद नहीं किया गया था। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रेल ने 23 मार्च 2020 से सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया था। बहरहाल, देश के विभिन्न भागों तक अनिवार्य पण्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियां बंद नहीं की गई थीं।

(घ) और (ड.): 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 810.31 हेक्टेयर रेल भूमि का अतिक्रमण किया गया था, जिसमें गरीब लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण शामिल है।

सरकार, विभिन्न स्तरों पर नियमित निरीक्षण करके इस प्रकार अतिक्रमण की गई भूमि की पहचान करती है। यदि कोई उल्लंघन ध्यान में आता है, जिसका अंततः अतिक्रमण हो सकता है, उसे उसी समय वहां से हटा दिया जाता है।

यदि यह अतिक्रमण झुग्गियों, झोपड़ियों और अवैध आवास के रूप में अस्थाई स्वरूप (सॉफ्ट अतिक्रमण) का होता है, तो उसे रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के परामर्श एवं सहायता से हटवा दिया जाता है। पुराने अतिक्रमणों के लिए, जिनमें पार्टी को समझा-बुझाकर मनाया नहीं जा सकता हो, तो ऐसे मामलों में समय-समय पर यथा आशोधित सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) के तहत कार्रवाई की जाती है।

रेलों की परिचालनिक और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं के कारण रेल भूमि पर अतिक्रमण करने वालों का पुनर्वासन और स्थापन संभव नहीं है। आवास व्यवस्था राज्य का विषय है और पुनर्वासन/पुनर्स्थापन के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने के साथ-साथ इसकी लागत को वहन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों अथवा संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की होती है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2018, 2019, 2020 एवं चालू वर्ष अर्थात 2021 (नवंबर तक) के दौरान रेल सुरक्षा बल के सहयोग से इंजीनियरी विभाग द्वारा कुल 5290 संयुक्त अभियान चलाए गए थे जिनमें रेल क्षेत्र से कुल 10,832 अतिक्रमण हटाए गए हैं।

*****

**श्री कामाख्या प्रसाद तासा** : उपसभापति महोदय, मैंने मंत्री जी का जवाब पढ़ा है। मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। सर, पूरे देश में encroachment एक बहुत बड़ी समस्या है। जो poor people हैं, जो बी.पी.एल. लेवल के नीचे हैं, उन लोगों के द्वारा encroachment होता है। उन्होंने जवाब दिया है कि alternative rehabilitation के लिए state government और urban bodies responsible हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उससे रेलवे की बातचीत होती है? **...(व्यवधान)...**

**श्री उपसभापति** : तासा जी, अभी केवल एक ही प्रश्न पूछिए।

**श्री अश्वनी वैष्णव** : सर, ऑनरेबल मेम्बर ने जो concern raise किया है, मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में ऐसे करीब दो-तीन राज्य हैं। मुम्बई में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छा encroachment removal हुआ है। इसके साथ ही सूरत के पास उदना में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से encroachment removal हो रहा है। यह समस्या आज की नहीं है। Encroachment on railway land बहुत पुरानी समस्या है। इसको बहुत sensitively और संवेदना के साथ डील किया जा रहा है। कहीं पर भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि किसी के ऊपर अचानक कोई मार पड़े।

**श्री उपसभापति** : तासा जी, आप अपना सेकंड सप्लीमेंटरी पूछिए और केवल एक ही सवाल पूछिएगा।

**श्री कामाख्या प्रसाद तासा** : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या encroachment land को vacant किया गया है? क्या इसमें dry port या car parking के लिए रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ सोचा गया है और क्या भविष्य में unemployment की problem को संस्थापित करने का कोई प्लान है?

**श्री अश्वनी वैष्णव** : उपसभापति महोदय, पटरी के दोनों तरफ narrow strip में encroachment होता है, ऐसा अभी तक observe किया गया है। जो land free होता है, वह mostly किसी न किसी नए प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। मान लीजिए कि doubling करनी है, थर्ड लाइन बिछानी है या electrification के लिए थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो वह उसके लिए यूज़ होता है। जहां पर भी संभव हो, पार्किंग या दूसरी कोई facility के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, during lockdown, I would say that many B-class stations or unmanned stations and local trains have been shut down or stopped or whatever it is.

**श्री उपसभापति** : प्लीज़, पीछे बैठकर आपस में बात न करें।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: I am talking about Assam particularly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: In Assam, I have seen that the local passengers who are travelling for jobs, medical treatment and education are facing a lot of problems. In another part of the country, B-class railway stations have been opened and local trains are running.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put your question. You have to put your question.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: What is the intention of the Government about Assam? I may cite some examples like Dangori-Tinsukia, Jorhat-Tinsukia, Tinsukia-Naharlagun, Simaluguri-Dibrugarh Town, Rangia-Guwahati, etc. They are all shut down and stopped. So, encroachers are also taking advantage of the situation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

**श्री अश्वनी वैष्णव** : उपसभापति महोदय, नॉर्थ-ईस्ट के लिए भारतीय रेलवे ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कदम उठाया है। पहली बार प्रत्येक नॉर्थ-ईस्ट के कैपिटल तक रेल ले जाने की परिकल्पना पर जोरों से काम चल रहा है। बहुत तेजी से काम चल रहा है। मेरे साथी यह भी जानते हैं कि किस तरह से पहली बार इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजलीकरण असम तक पहुंचा है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, this is a separate issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

**श्री अश्वनी वैष्णव** : पिछले साल, चाहे डब्लिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशन्स का डेवलपमेंट हो या चाहे कोई भी aspect हो, नॉर्थ-ईस्ट में और especially असम के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आपने पूछा कि असम के लिए intent क्या है, that is why I am clarifying this. असम बहुत important State है और उसका रेलवे के प्रोजेक्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

**श्री उपसभापति** : माननीय शक्तिसिंह गोहिल जी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, I want a specific answer.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, he has left one supplementary.

**श्री उपसभापति :** प्लीज़...(**व्यवधान**)...माननीय मनोज जी, उन्होंने जो सवाल पूछा है, उसके लिए उनको मौका दे दिया गया था। ...(**व्यवधान**)... सवाल उनका नहीं था और आप लोग जब भी हस्तक्षेप करते हैं, तो कृपया ध्यान रखें कि दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है।

**SHRI AJIT KUMAR BHUYAN:** This is not an answer, Sir.

**श्री शक्तिसिंह गोहिल** : माननीय उपसभापति महोदय, कोरोना के वक्त में platform tickets ले लेकर अन्य चीज़ों के दाम जो अभूतपूर्व रूप से बढ़ाए गए हैं और जो गुजरात की ट्रेनें कोरोना के वक्त में बंद हुई हैं, इसके संबंध में मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि जब सारी फ्लाइट्स private operators ने भी नॉर्मल कर दी हैं और सब नॉर्मल हो गया है, तो गुजरात में जो ट्रेनें बंद हुई हैं, वे कब शुरू होंगी और कोरोना के वक्त में आपने जो अभूतपूर्व दाम बढ़ाए हैं, platform tickets से लेकर और चीज़ों के, उनको आप कब कम करेंगे?
**श्री अश्वनी वैष्णव** : सर, माननीय सदस्य हाउस को सही सूचना नहीं दे रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह पहली बार नहीं है, इससे पिछले प्रश्नों में भी इस तरह से किया गया। ...(**व्यवधान**)... यह अच्छी बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, what is this? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

**श्री अश्वनी वैष्णव** : सर, कोरोना के टाइम में देश भर में भारतीय रेलवे ने जिस तरह से - चाहे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे श्रमिक स्पेशल्स चलाकर देश के सारे के सारे माइग्रेन्ट लेबर्स को पहुंचाने का काम हो।...(**व्यवधान**)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sir, I have a specific question. ...(*Interruptions*)... My question was specific. ...(*Interruptions*)...

**श्री अश्वनी वैष्णव** : चाहे लॉकडाउन के टाइम में सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो। क्या इस काम को आप नकार सकते हैं? सर, इसे कोई नहीं नकार सकता है। यह बहुत ही अच्छा काम था।...(**व्यवधान**)...

**श्री शक्तिसिंह गोहिल** : सर, मेरा क्वेश्चन क्या है और मंत्री जी क्या बोल रहे हैं?

**श्री अश्वनी वैष्णव** : सर, जहां तक प्लेटफॉर्म टिकट की बात है, आज की तारीख में प्लेटफॉर्म टिकट देश भर में सब जगह सामान्य लेवल पर है। ...(**व्यवधान**)...प्लीज़, आप सुन तो लीजिए।...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति :** प्लीज़, बीच में डिस्टर्ब न करें। ...(**व्यवधान**)... Address to the Chair. ...(*Interruptions*)...

**श्री अश्वनी वैष्णव** : सर, लंबे टाइम से इस तरह की facility, इस तरह का empowerment DRMs को दिया गया था, जो आज से नहीं, बल्कि 30-40 वर्षों से है कि जब भी उनको crowd control करना हो या कहीं स्टेशन्स पर थोड़ा ध्यान रखना हो, तब वे temporarily उसे बढ़ा सकते हैं। जहां-जहां भी इसे temporarily बढ़ाया गया था, वहां पर already platform ticket का दाम कम कर दिया गया है।

**श्री राम विचार नेताम** : महोदय, मेरा एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है। लॉकडाउन के बाद सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में चलनी शुरू हुईं और जहां एक ओर स्पेशल ट्रेन का यात्री किराया काफी अधिक है, वहीं लोगों को रिज़र्वेशन नहीं मिलता और गाड़ियां पूरी खाली रहती हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप कब उसे सामान्य तरीके से बहाल करेंगे, चलाना शुरू करेंगे और इसके साथ ही साथ जो यात्री सुविधा मिला करती थी...

**श्री उपसभापति :** राम विचार नेताम जी, आप एक ही सवाल कीजिए। एक सवाल में दो सवाल न पूछा करें।

**श्री राम विचार नेताम :** जैसे bed roll और जो बाकी सुविधाएं थीं, आप उन सुविधाओं को कब से बहाल करेंगे? यहां ज्यादातर आदमी तो ट्रेन से ही यात्रा करते हैं।

**श्री अश्वनी वैष्णव** : इस प्रश्न में बहुत सारे अलग-अलग विषय उठ रहे हैं। ऑलरेडी normal express और mail trains normal fare पर चल रही हैं। माननीय सांसद महोदय को अपना डेटा अपडेट करना चाहिए। सर, वह already normalize हो चुका है और रही बात bed roll की, हम लोग bed roll चालू करने वाले थे, लेकिन जैसे ही यह Omicron का threat आया है, तो हम लोग इसमें बहुत सोच-समझकर steps लेंगे। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसके ऊपर कोई हड़बड़ी में step लिया जाए। यह देश की सुरक्षा का सवाल है, सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा का सवाल है।

**श्री उपसभापति :** क्वेश्चन नम्बर 140